(IX) दलितों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा व्यवस्था तत्काल लागू हो। दलित के लिए दलित क्षेत्रों के स्कूलों में बेहतर सुविधाएँ हो और व्यवसायिक एवं तकनीकि शिक्षा

(X) के जरिए दलितों को शिक्षा दी जाए। दलित बच्चों के लिए छात्रवृत्तियों तथा निरक्षरों की संख्या के अनुपात को देखते हुए धन राशि आवंटित किया जाए।

(XI) सरकारी एवं निजी विद्यालयों एवं तकनीकी एवं व्यवसायिक सं दलित बच्चों के प्रवेश हेतु आरक्षण लागू किया जाए। सरकारी खर्च पर कम आमदनी वाले परिवारों के बच्चों को भी अच्छी शिक्षा प्रदान कि जाए। अंग्रेजी माध्यम वाले सभी स्कूलों में दलितों के बच्चों को दाखिलों में पर्याप्त प्रतिनिधित्व किया जाए।

5/4/19

(Xi) दलित महिलाओं को विशेष महिला श्रेणी में शामिल किया जाए। उसके मुताबिक जनगणना रिपोर्ट और विकास रिपोर्ट में उनके लिए अलग से आकड़े हो इन्हें विकास योजनाओं द्वारा मुख्य धारा से जोड़ने के उपाय किए जाए। राष्ट्रीय एवं राज्य महिला व आयोग को निर्देश दिया जाए कि वे इस श्रेणी की महिलाओं को

Scanned with CamScanner

स्थिति स्थिति का आंकलन अपनी वार्षिक रिपोर्ट में प्रस्तुत किए

(12) अनुसूचित जाति, जनजाति अत्याचार अधिनियम 1989 एवं 1995 को कड़ाई से लागू किया जाए। जातियों हिंसा व हिंसा फैलाने वाले दंबग लोगों और उनके साथ रिश्ता रखने वाले पुलिस अधिकारियों पर मुकदमें चलाए जाए। दलितों पर जुर्म या अत्यचार करने वाले मामलों पर दोषियों पर सामूहिक दण्ड जैसी व्यवस्था कि जाए। जिससे अत्यचारी कानून को चकमा न किया जाए।

(13) विश्व विद्यालयों और सार्वजनिक प्रतिष्ठानों में दलितों का उचित प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया जाए। इस नियम का जो संस्थाएं पालन न करें उनकी मान्यता समाप्त कर दी जाए। और उन्हें मिलने वाले अनुदान को भी बंद कर दिया दिया जाए। निजी उद्योगों या व्यवसाय इकाईयों में में भी इसी तरह की व्यवस्था तत्काल लागू की जाए।

(14) राष्ट्रीय एवं सभी राज्यों की बजट दलितों की आबादी के अनुसार उसी के हिसाब से राशि तय की जाए। इस राशी का अन्य जगह दुरुपयोग करने वाले के ~~विरु~~ विरुध कठोर करावाई कि जाए।

MY SCHOLAR

Scanned with CamScan